

## 11 MAY, 2019 THE HINDU RESOLVING INDIA'S BANKING CRISIS

### संदर्भ-

- NPA की समस्या के समाधान के बिना आर्थिक विकास में तेजी संभव नहीं है।
- बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े एक अत्यंत गंभीर समस्या का सामना भविष्य में गठित होने वाली नई सरकार को करना पड़ सकता है। वस्तुतः नई सरकार द्वारा ही शायद इस समस्या के समाधान को लेकर कोई ठोस उपाय अपनाए जाएंगे जिससे प्रभावकारी रूप से इस समस्या से निजात प्राप्त हो सकेगा।
- एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2018 में वाणिज्यिक बैंकों के पास NPA की मात्रा 11.2% थी जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास इसकी मात्रा 86% तक थी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास NPA के अग्रिम अनुपात में वर्ष 2007-08 की तुलना में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि वर्तमान में 14.6% तक बढ़ी है।
- NPA में यह वृद्धि चौका देने वाली है। प्रश्न यह है कि यह कैसे घटित हुआ?

### संकट की शुरुआत

- 2004-05 से 2008-09 के अवधि के मध्य वाणिज्यिक ऋण दोगुना हो गया। यह ऐसी अवधि थी जब विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था फलफूल रही थी। भारतीय फर्मों ने आने वाले अवसरो का लाभ उठाने के लिए अधिक मात्रा में कर्ज प्राप्त किया। अधिकतर निवेश बुनियादी ढाँचा, दूरसंचार, बिजली, सड़क, विमानन, इस्पात जैसे आधारभूत संरचनाओं में किया गया।
- अति उत्साही व्यवसायी वर्ग आंशिक रूप से तर्कसंगत और आंशिक रूप से तर्कहीन था। अन्य लोगों की तरह उनका भी मानना था कि भारत 9% वार्षिक वृद्धि के एक नए युग में प्रवेश कर गया है।
- 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ चीजें गलत होने लगीं। भूमि अधिग्रहण तथा पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में पैदा हुई समस्याओं के कारण बहुत सी परियोजनाएं ठप हो गईं तथा समय के साथ उनकी लागत भी बढ़ गई।
- 2007-08 में वैश्विक वित्तीय संकट की शुरुआत हुई और 2011-12 के बाद वृद्धि में मंदी के साथ राजस्व के पूर्वानुमानों में कमी हुई। इस परिदृश्य में भारत ने अपने नीतिगत दरों को कड़ा किया जिससे वित्तीय लागत बढ़ी। रुपए के मूल्यहास से उन कंपनियों को नुकसान हुआ जिन्होंने विदेशी मुद्रा में लोन उधार लिया था। क्योंकि रुपए के मूल्यहास से वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों और सेवाओं को तरजीह मिली जिससे निर्यात को बढ़ावा मिला आधारभूत संरचनाओं में अत्यधिक निवेश का फायदा तात्कालिक रूप से रुपए के मूल्यहास से प्राप्त नहीं हो पाया। प्रतिकूल कारकों के इस संयोजन ने कंपनियों के लिए भारतीय बैंकों को ऋण देना मुश्किल बना दिया।
- चूंकि समस्या PSB's के लिए अधिक केन्द्रित है इसलिए कुछ लोगों ने तर्क दिया कि सार्वजनिक स्वामित्व को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इससे भ्रष्टाचार और अक्षमता को बढ़ावा मिलता है।
- इसलिए बैंकों का निजीकरण किया जाना चाहिए। इस समाधान के साथ समस्याएं हैं- उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी बैंक SBI का 2018 में सकल NPA/अग्रिम अनुपात 10.9% था जबकि निजी क्षेत्र के बैंक ICICI का 9.9% एक विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का अनुपात 11.7% था जो SBI की तुलना में अधिक था।
- PSB's के लिए - खनन, लोहा और इस्पात, वस्त्र, बुनियादी ढांचे और विमानन क्षेत्र जैसे पाँच क्षेत्र अत्यधिक जोखिम भरे रहे।

### मानदंड की कसौटी-

- वर्ष 2014-15 में NPA के संदर्भ को एक विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, जब RBI के द्वारा NPA को नियंत्रित करने हेतु एसेट क्वालिटी रिव्यू के अंतर्गत मानदंडों को लाया गया। क्योंकि NPA को लेकर

तात्कालिन समय में RBI के द्वारा ऐसा प्रदर्शित किया गया कि यह अधिक मात्रा में बैंकिंग तंत्र में शामिल नहीं है।

- 2015-16 में NPA अपने पिछले वर्ष के अवधि की तुलना में लगभग दोगुना हो गया।
- यह अचानक नहीं हुआ इसके कारणों की समीक्षा अतीत में लिए गए निर्णयों में समाहित है।
- उच्च NPA के कारण विशेष रूप से PSB ने घाटा उठाना शुरू कर दिया, परिणाम स्वरूप उनके पास पूँजी की कमी होने लगी। सरकार द्वारा बैंकों में पूँजी के निवेश की रफ्तार धीमी थी और यह न्यूनतम पूँजी के नियामक मानदंडों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त भी थी।
- पर्याप्त पूँजी के बिना बैंकों को ऋण देने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सकल NPA/अग्रिम अनुपात के अंश में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। इन कारणों से यह अनुपात संकट के स्तर पर पहुँच गया है।
- कर्ज के NPA हो जाने के बाद उसे जल्द हल करना महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च ब्याज की दर के फलस्वरूप NPA तेजी से बढ़ता है।
- बुनियादी ढांचा परियोजनाएं वैश्विक वित्तीय संकट और पर्यावरण, भूमि अधिग्रहण के मुद्दों से प्रभावित थीं। इसके अलावा, खनन और दूरसंचार अदालती निर्णयों से प्रभावित थे। चीन के डंपिंग से स्टील प्रभावित हुआ था। इस प्रकार, जिन क्षेत्रों में पीएसबी प्रभावी थे, वे बैंक प्रबंधन के नियंत्रण से परे कारकों से प्रभावित थे।

### ऐसे संकटों को रोकने की योजना

- पीएसबी का निजीकरण समस्या का समाधान नहीं है। इसमें मध्यम अवधि के दौरान कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ तात्कालिक और दीर्घकालिक अवधि उपायों की भी आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य ऐसे संकटों की पुनरावृत्ति को रोकना है।
- एक तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। एनपीए को हल करने के लिए बैंकों को ऋण पर नुकसान उठाना पड़ता है। बैंकों को जांच एजेंसियों द्वारा उत्पीड़न के डर के बिना हेयर कट के संदर्भ में निर्णय लेने की आजादी होनी चाहिए।
- इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने बड़े कर्जदाताओं के रिजॉल्यूशन प्लान्स की देखरेख के लिए छह-सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इसमें तेजी लाने के लिए, ऐसे और पैनलों की आवश्यकता हो सकती है। एक विकल्प संसद के एक अधिनियम के माध्यम से आवश्यक होने पर एक ऋण समाधान प्राधिकरण स्थापित करना भी है। दूसरा, सरकार को बैंकों के पुनर्पूँजीकरण के लिए जो भी अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता होती है, उसे एक बार में पूरा करना होगा- ऐसी पूँजी को कई किशतों में प्रदान करना सहायक नहीं है।
- मध्यम अवधि में, आरबीआई को संकेतकों की निगरानी के लिए बेहतर तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- यह एक सरल संकेतक, क्रेडिट विकास की दर होगी जो क्रेडिट की वृद्धि की दर या अर्थव्यवस्था की व्यापक विकास दर के अनुरूप है।
- सामान्य रूप से PSB's बैंकों के कामकाज को मजबूत करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे PSB बोर्डों की कार्यप्रणाली, निश्चित रूप से सुधर सकती है। एनपीए के मामले में पिछले एक दशक के अनुभव से महत्वपूर्ण सबक जोखिम का प्रबंधन है।
- किसी भी व्यावसायिक समूह, भौगोलिक क्षेत्र, आदि के लिए अत्यधिक जोखिम - पूरी तरह से बैंक बोर्डों पर छोड़ दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। आरबीआई ने कुछ हद तक यह सबक लिया है।
- जोखिम के अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाना बाकी है। PSB's में समग्र जोखिम प्रबंधन को उच्च स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। इसके लिए निश्चित रूप से पीएसबी बोर्डों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें पीएसबी बोर्डों पर अधिक उच्च गुणवत्ता वाले पेशवरों का शामिल करने और उन्हें बेहतर पारिश्रमिक देने की आवश्यकता है।

- शीर्ष प्रबंधन के चयन के बारे में सलाह देने के लिए बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के गठन के बावजूद, प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति में लंबे समय से देरी हो रही है। यह समाप्त होना चाहिए।
- आर्थिक विकास को गति देने का कार्य अत्यावश्यक है। यह उन समस्याओं का हल खोजे बिना संभव नहीं है जिसका बैंकिंग प्रणाली सामना कर रही हैं। सार्वजनिक स्वामित्व के ढांचे के भीतर प्रदर्शन में सुधार के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। सरकार की ओर से त्वरित ध्यान देने की आवश्यकता है।

#### विशेष-

- **NPA ( गैर-निष्पादित परिसंपत्ति )**- जब कोई बैंक का कर्जदार अपने कर्ज की EMI 90 दिनों तक देने में असमर्थ होता है तो इस प्रकार का दिया गया ऋण NPA कहलाता है।
- **हेयरकट** - जब कोई वित्तीय संस्थान किसी को कर्ज देती है और दिये हुए कर्ज को वापस मिलने की संभावना कम होती है, तब दिये गये मूलधन तथा ब्याज की रकम को एक सीमा तक कम कर दिया जाता है, जो रकम कम की जाती है उसे ही हेयरकट कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी को 100 रु. का कर्ज दिया गया तो उसे वापस लेने के लिए 100 रु. का तात्कालिक बाजार मूल्य 80 रु. लगाकर कर्ज की वापसी सुनिश्चित की जाती है यही 20 रु. की कमी हेयरकट कहलाती है।

#### मुख्य परीक्षा प्रश्न

**प्रश्न-** भारत में बैंकिंग क्षेत्र की समस्या और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के मध्य विकास दर को 9% से आगे ले जाना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। उपर्युक्त संदर्भ में सरकार और RBI द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कीजिए

